THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) Municipal Corporation of Delhi has carried out a survey of the recently and has reported more than 1300 premises which have come up unauthorisedly in the area during last 20 years.

(c) MCD has reported that its Building Department has been taking action against the unauthorised construction in the Sainik Farms from time to time depending upon the availability of police assistance. The MCD has demolished 39 buildings and 70 boundary walls since March, 1993.

Allotment of Flats under self Financing Schemes

217. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that registrants who have applied for allotment of flats under Self Financing Schemes of the Delhi Development Authority have yet not got the flats;

(b) the number of Self Financing Schemes announced by the authority so far;

(c) what is the amount collected under various Self Finaninceg Schemes by the Authority; and

(d) whether any interest is being paid to the registrants who have deposited money under SFS?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir. While many registrants have been allotted flats, some remain to be allotted.

(b) 8 Self Financing Schemes have been announced by DDA so far.

(c) Rs. 90.84 crores.

(d) Yes, Sir.

दिल्ली में आवासीय इकाइयां

218. **श्री रामनरेश यादव**: क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक दिल्ली में कितनी आवासीय इकाईयों की आवश्यकता होने का अनुमान है; और

(ख) दिल्ली में आवासीय इकाईयों के निर्माण के संबंध में सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पो० के० थुंगन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली की वृहद् योजना–2001 के अनुसार, 1991–96 के दौरान अनुमानित अतिरिक्त जनसंख्या के लिए 4.34 लाख रिहायशी इकाईयों की आवश्यकता है।

(ख) भारत सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मकानों के निर्माण के लिए अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 8वीं योजना के अन्त तक 15-7-93 की बकाया स्थितिनुसार विभिन्न श्रेणी के मकानों हेतु 8वीं योजना अवधि के अन्त तक बकाया 73003 पंजीकृत व्यक्तियों को मकान दिए जाने की आशा है बशर्ते कि नरेला फेज 1-बी, रोहिणी फेज 4 तथा 5 में भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाए और नागरीय प्राधिकरणों द्वारा मुख्य सेवाएं, जल-मल व्ययन, जलापूर्ति, जल निकास, सड़कें तथा बिजली जैसे अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं दे दी जाएं। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण का योजना अवधि के दौरान, मकानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए द्वारका में 400 सहकारी सामुहिक आवास स्थितियों को भी भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव है।